राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक डा. कल्ला का कार्यकाल एक वर्ष बढा

जयपुर, 22 अप्रेल2010, राज्यसरकार ने गुरुवार को जारी आदेश द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक डा. सुधीर कुमार कल्ला के कार्यकाल में एक वर्ष के लिए वृध्दि की है। सुदक्ष एवं अनुभवी अभियंता व कुशल प्रशासक डा. कल्ला 23 अप्रेल 2008 से इस पद पर कार्यरत है।

इनके कार्यकाल में राज्य के बिजलीघरो का परिचालन एवं संधारण काफी अच्छा रहा है तथा नई परियोजनाओं के निर्माण कार्य ने गति पकडी है। इस दौरान 125 मेगावाट की गिरल –2, 250 मेगावाट की सूरतगढ–6, 195 मेगावाट की कोटा–7 और 250 मेगावाट की छबडा–1 इकाई से विद्युत उत्पादन आरम्भ कर दिया गया है।

वर्तमान में प्रत्येक 250 मेगावाट क्षमता की छबडा में 3 इकाइयों तथा प्रत्येक 600 मेगावाट क्षमता की कालीसिन्ध, झालवाड में 2 इकाइयों का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। इसके साथ ही रामगढ गैस थर्मल पावर स्टेशन की विस्तार योजना के अंतर्गत तृतीय चरण में 160 मेगावाट क्षमता बढाने के लिये एक गैस तथा एक स्टीम इकाइ लगाने के लिए मुख्य उपकरणों की आपूर्ति तथा स्थापना और बैलेन्स आफ प्लांट कार्य के लिए क्रमशः भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड एवं सुभाष प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को कार्य आदेश जारी कर दिए गए है। छबडा, झालावाड और रामगढ की इन इकाइयों से वर्ष 2010–12 में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किए जाने का लक्ष्य है।

इसके साथ ही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सुपर क्रिटिकल ताप इकाइयों की स्थापना– परियोजना के लिए प्रत्येक 660 मेगावाट क्षमता की सूरतगढ और छबडा में दो–दो इकाइयों के लिए राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने अंतरराष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित कर ली है जिनका परीक्षण एवं मूल्यांकन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना में सूरतगढ, कालीसिन्ध–झालावाड, बांसवाडा, धौलपुर और रामगढ में नई इकाइयों की स्थापना के लिए विद्युत उत्पादन निगम को सैध्दान्तिक स्वीकृति प्रदान की है जिनकी कुल क्षमता 4450 मेगावाट है। इनमें से सूरतगढ, बांसवाडा व झालावाड में सुपर क्रिटिकल ताप इकाइयां लगाई जायेगी।

डा. कल्ला के कार्यकाल में वृध्दि का विद्युत निगमो के अभियंताओं, अधिकारियों और कर्मियों ने स्वागत करते हुए राज्य सरकार का विशेषकर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है। आशा व्यक्त की गई है कि राज्य सरकार के इस निर्णय से राज्य के विद्युत विकास को बढावा मिलेगा।

———